में उत्तरप्रदेश में उद्योगों की स्थापना के मूल कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या ;

(ग) उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना की मूल योजनायें क्या थीं ; और

(घ) क्या उद्योगों के लिये धनराशि और बढ़ा दी गयी है ?

**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९३] ।

**Shri S. N. Chaturvedi:** May I know whether the additional amount will have to be borne by the State Government and will be at the expense of other items?

**Shri Hathi:** It will be within the ceiling and will be borne by the State Government.

**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, इस विवरण में बताया गया है, कि उत्तर प्रदेश के लिये ८० लाख ३९ हजार रुपया उद्योगों के लिये और रखा गया है, लेकिन यह रकम जो प्लान का टोटल एलाटमेंट है उनके ही भीतर रहेगी इसका यह मतलब हुआ कि और मदों में से काट कर यह रकम उद्योगों के लिये रखी जा रही है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश के लिये प्लान के टोटल एलाटमेंट को भी बढ़ाने का विचार सरकार कर रही है ?

**Shri P. K. Deo:** I request that S.Q. No. 1321 may be taken up.

**Mr. Speaker:** All right.

**Food Parcels to China**

***1321. Shrimati Savitri Nigam:** Will the **Prime Minister** be pleased to state whether Government are permitting the despatch of large number of food parcels to China by Chinese staying in India?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh):** Yes, Sir; we are aware that a large number of food parcels are being sent to China by members of the Chinese Community in India. The despatch of such parcels is permissible under our regulations. Specially on humanitarian grounds, we do not consider it proper to place any restrictions on the despatch of food parcels to China at this time.

**Shri P. K. Deo:** In view of the failure of crop and scarcity of food in China, are we considering the relaxation of our export rules?

**Mr. Speaker:** He has not said that—no question of relaxing the rules.

**The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru):** No question has arisen, nor is it likely to arise.

**Shri Hem Barua:** On humanitarian considerations, because China is experiencing a famine and there is large exodus from China, are Government considering sending some relief from our country?

**Mr. Speaker:** That is a suggestion for action.

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

**डा० आम्रो का हत्यारा**

***१३०९. श्री विभूति मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० आम्रो को मारने वाले का पता लगा लिया गया है ; और

(ख) क्या उनकी हत्या में नागा विद्रोहियों के अतिरिक्त विदेशी तत्वों का भी हाथ था ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री स० चु० जमीर)** : (क) डा० इम्कोंगलिबा आम्रो की हत्या के सम्बन्ध में तीन व्यक्तियों पर सन्देह था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ।

(ख) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

**ड्राफ्टसमैन प्रशिक्षण परीक्षा**

२६३५. **श्री गहमरी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा ली जाने वाली ड्राफ्टस्मैन प्रशिक्षण परीक्षाओं में प्राइवेट उम्मीदवारों को भी बैठने की सहूलियत थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नियम भविष्य में भी जारी रहेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण ?

**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) अब नहीं ।

प्राइवेट उम्मीदवारों को जनवरी, १९६२ तक ही ड्राफ्टस्मैन (सिविल और मैकेनिकल) की अखिल भारतीय प्रशिक्षण परीक्षाओं में बैठने की सहूलियत थी । इन परीक्षाओं में असफल होने वाले उम्मीदवारों को दो अवसर और दिये जायेंगे ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ड्राफ्टस्मैन (सिविल) और ड्राफ्टस्मैन (मैकेनिकल) व्यवसायों में मिलने वाले कामकाज के अवसरों में कमी आने के कारण, तथा इसलिये भी कि पोलिटेक्नीक और इंजीनियरी कालेजों में इन व्यवसायों का सिखाना आरम्भ हो गया है, राज्यों के प्रतिनिधियों ने अपनी छठी बैठक में, जो २१ से २३ अगस्त, १९६१ के बीच नयी दिल्ली में हुई थी सिफारिश की कि प्राइवेट उम्मीदवारों को दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के मातहत चलायी जाने वाली अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षाओं में नहीं बैठने दिया जाये ।

इस सिफारिश को सरकार ने मान लिया है और जनवरी १९६२ के बाद होने वाली सभी व्यवसायिक परीक्षाओं पर इसे लागू कर दिया गया है ।

**Scheme for Economic Development of Districts**

**2636. Shri M. K. Kumaran:** Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether Planning Commission have evolved any scheme to develop different types of economic activities in each district in a co-ordinated manner; and

(b) what steps have been taken by Central and State Governments to carry out this scheme?

**The Minister of Planning and Labour and Employment (Shri Gulzarilal Nanda):** (a) and (b). Each State Government normally prepares district plans and plans for blocks which fall within the framework of its five-year plan for the State as a whole. At the district level, co-ordination is achieved through the Zila Parishads. The block serves as a unit of development for several rural programmes and co-ordination is achieved through block plans formulated by Panchayat Samitis.

**Rural Housing Scheme**

**2637. Shri Ulaka:** Will he Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state:

(a) the Central assistance given to the Government of Orissa for granting loans for improvement of houses under the Rural Housing Scheme during the Second Five Year Plan Period; and

(b) the allocation of funds made under the Third Five Year Plan for grant of subsidy to the Government of Orissa for securing house sites for landless agricultural workers?

**The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Jaganatha Rao):** (a) A total